

Archaeological Congress were replaced changing the name of the persons to inaugurate it; and

(b) how Government propose to deal with a section of archaeologists who, in the name of secularism, have generated a controversy about WAC and thus hurt the cause of archaeology in India and abroad?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Late receipt of non-acceptance of the original request for the inaugural function led to the replacement of invitation cards.

(b) The World Archaeological Congress-3 at Delhi has since concluded. This Congress is an independent body of academicians and scholars. Differences among them, if any, can be tackled only by that body.

बिहार के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के साथ संबद्ध किया जाना

2831. श्री रामदेव मंडारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भौगोलिक दूरी को देखते हुए, बिहार के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संबद्ध करने का क्या औचित्य है, जबकि गाजियाबाद/ कलकत्ता कार्यालय इसके लिए बेहतर स्थान सिद्ध होंगे ; और

(ख) क्या सरकार बिहार के महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाजियाबाद / कलकत्ता कार्यालय के साथ संबद्ध करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी सैलजा)

(क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार आयोग ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना और उनकी कार्यपद्धति के लिए योजना की जाँच हेतु एक अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया है। इस समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गाजियाबाद, गुवाहाटी, भोपाल, पुणे और हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

उपयुक्त शहरों में 5 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय किया। हालाँकि इस मामले पर पुनः विचार करने के पश्चात् आयोग ने कलकत्ता में एक और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उड़ीसा में स्थित विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल होंगे।

Objectionable Literature Prescribed for School in Assam

2832. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have been monitoring the implementation of its Operation Black Board Scheme;

(b) if so, what are the details of its implementation in each State during the last three years;

(c) whether Government's attention has been drawn to a report published in the Indian Express of September 25, 1994 captioned 'learning about the birds and bees in Assam';

(d) whether the text books prescribed under the Operation Black Board Scheme in Assam for children in the age group of 6 to 10 contain undesirably explicit sexual descriptions;

(e) if so, what are the details in this regard;

(f) whether such objectionable literature under the scheme has been prescribed for the children in any other State, if so, what are the details in this regard; and

(g) what steps Government have taken to check the publication and circulation of such literature in States under the above Scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) The information is given in statement (See below).

(c) Yes, Sir.

(d) & (e) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(f) No such case has come to the notice.

(g) Does not arise.